The International Journal of Advanced Research In Multidisciplinary Sciences (IJARMS)

Volume 1 Issue 1, 2018

Xkkeh.k Hkkjr esa thfodk dh igqap rFkk U;wu 0;; oxZ esa ÅtkZ vUrxzg.k dk Lrj

M,- egEen 'kehe

एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य

राजकीय महाविद्यालय, महाराजगंज

lUnHkZ

जिन राज्यों में खाद्यान्नों का उत्पादन कम होता है वहाँ पर निम्न आय वर्ग कम कैलोरी अन्तर्ग्रहण की समस्या से प्रभावित होता है यद्यपि उस राज्य का औसत उपयोग पर्याप्त होता है। न्यूनतम 5 प्रतिशत जनसंख्या के कैलोरी अन्तर्ग्रहण के साथ–साथ औसत रुप से राज्य में कैलारी अन्तर्ग्रहण प्रति व्यक्ति अनाजों के शुद्ध उत्पादन से महत्वपूर्ण रुप में सम्बंधित है। इसका दो मुख्य कारण है– जो पर्याप्त कैलोरी अन्तर्ग्रहण में सक्षम बनती है, पहला, उत्पादन के क्षेत्रों में कीमते सम्भवतः कम होती है जो गरीबो को पर्याप्त अन्तर्ग्रहण में सक्षम बनती है, दूसरा पर्याप्त जीविका अवसर वाले क्षेत्रों में न्यूनतम व्यय वर्ग की पर्याप्त या अधिक कैलोरी अन्तर्ग्रहण की सम्भावना भी अधिक होती है।

iLrkouk

खाद्य पहुँच खाद्यान्नों के खरीदने की क्षमता पर निर्भर करती है जो जीविका पहुँच (Livelhood Acess) से जुड़ा हुआ है। जीविका पहुँच कोई रोजगार नहीं है बल्कि दीर्घ अवधि में आय के निश्चित पहुँच को व्यक्त करता है। जिसका महत्व दीर्घकालीन जीविका पहुँच के द्वारा खाद्य को खरीदने की क्षमता को बढ़ाने में महत्व है। व्यक्ति बिना निर्वहनीय जीविका के गरीब बना रहता हैं। बेरोजगारी की अपेक्षा गरीबी एक बड़ी समस्या है जिसे उत्पादकीय जीविका के माध्यम से मुख्यतः हल किया जा सकता है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या उन व्यक्तियों को व्यक्त करता है जिसके पास उत्पादकीय जीविका (Productive Livelihood) की पहुँच नहीं है। गरीबी के कारण उनकी खाद्य तक पहुँच कम होती है, जिसके परिणाम स्वरुप उनकी खाद्य असुरक्षा और जोखिम (Vulnerability) भी अधिक होती हैं।

1. [kk| vlqj{kk vkSj xjhch dk e/; lEca/k (Relationship between Food Security and Poverty)

खाद्य असुरक्षा और गरीबी के मध्य सम्बंध काफी जटिल है तथा इसे एक दुष्चक्र (Vicious Cycle) के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि निर्धनता निःसंदेह रूप से भूख का एक कारण है जबकि अपर्याप्त खाद्य तथा उचित पोषण का अभाव स्वयं या अपने आप में गरीबी का एक अन्तर्निहत कारण है। भूख,

खाद्य असुरक्षा तथा कुपोषण गरीब लोगों को निर्धनता से बाहर निकलने में रोकते या बाधक है क्योंकि ये सब व्यक्ति के कार्य करने, सीखने तथा अपने पारिवारिक सदस्यों और अपनी देखरेख की क्षमता को कम करते है। लम्बें समय से भूखा व्यक्ति (Chronically Hungry People) गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम आवश्यक परिसम्पत्तियों (Necessary Assets) का निर्माण करने मे भी योग्य नही होता है। अतः खाद्य असुरक्षा निम्न प्रकार से गरीबी में वृद्धि करती है–

1. एक व्यक्ति को मूल भूत रूप से कार्य करने तथा उत्पादकीय (Productive) होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा अन्तर्ग्रहण (Sufficient Food Intake) और एक पर्याप्त पोषणीय स्तर की आवश्यकता होती है। कुपोषित व्यक्ति में लगातार कार्य करने की क्षमता नही होती है और इसलिए वह "एक सक्रीय और स्वस्थ जीवन" (An Active and Healthy Life) नही जी सकता है।
2. खराब पोषण (Poor Nutrition) खराब स्कूल प्रदर्शन (Performance) से भी सम्बंधित होता है क्योंकि भूख के कारण बालक निसक्रीय तथा थका हुआ होता है जो इसके सीखने या बौधिक (Cognitive) क्षमता को स्वयं बिगाड़ देती है। इसके परिणामस्वरूप बच्चें स्कूल में खराब प्रदर्शन करते है जिससे उसका भावी आर्थिक पुर्वानुमान या सम्भावनाएं (Prospect) बिगड़ जाती है और इस प्रकार खराब पोषण की प्रवृत्ति निम्न या कम आय से सम्बंधित होती है। जिसे निम्न चित्र की सहायता से समझा जा सकता हैं। जो www.fao.org से लिया गया हैं–

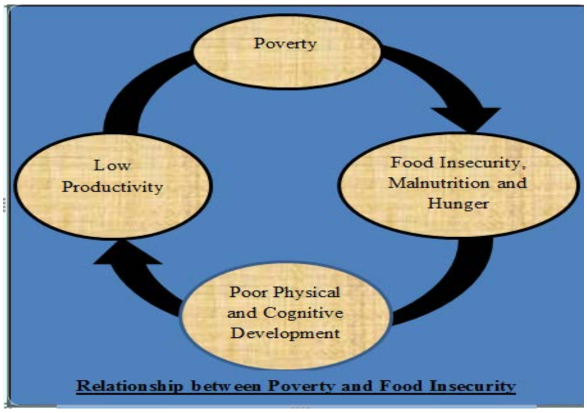

(Figure No. 1.1)

1. mnns'; vkj ifo/k (Objective& Methodology)

इस शोध पत्र के विश्लेषण का पहला उद्देश्य यह हैं कि ग्रामीण भारत के जिन राज्यों में गरीबी तथा श्रम आय पर निर्भर जनसंख्या अधिक हैं क्या उन राज्यों में– न्यूनतम व्यय वर्ग(Lower Expenditure Group) में जनसंख्या का ऊर्जा अन्तर्ग्रहण (Calorie Intake) भी कम है या नही।

जबकि दूसरा उद्देश्य ग्रामीण भारत के जिन राज्यों में गरीबी तथा श्रम आय पर निर्भर जनसंख्या अधिक हैं क्या उन राज्यों में–1890 कैलोरी से कम उपभोग करने वालें परिवारों का प्रतिशत भी अधिक हैं की नही।
इस शोध पत्र का विश्लेषण ग्रामीण भारत के मुख्यतः 17 राज्यों के मध्य द्वितीयक आकड़ों पर आधारित हैं जिसके विश्लेषण में मुख्यतः NSSO के आकड़ों का प्रयोग किया गया हैं तथा निष्कर्षो को ARC-View GIS Software के माध्यम से एक मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया हैं।

2. xjhch dk gsM dkmaV vuqikr (Head Count Ratio of Poverty)

निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे 'न्यूनतम स्तर' से नीचे गिर जाय जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएँ विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशो में भिन्न है। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है।

भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण या आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुए जैसे– अनाज, दालें, सब्जियाँ, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन है। यदि व्यक्ति इस निर्धारित कैलोरी से कम उपभोग करता हैं तो वह गरीब माना जाता हैं।

Table5.7		Livelihood Access Indicators in Rural India			
		1	2	3	4
S.N.	State/India	Headcount Ratio or %age Population Below Poverty Line in Rural India	Daily Status Unemployment Rate Per 1000 Persons in Labor Force	Average Daily Wage of Casual Labor other than Public Work (In Rs.)	%age of Household dependent on Labor Income-Agri.wage & Non- Agri wage / (%age Household of Casual labor)
		(2011-12)	(2011-12)		
	India	25.70	57	138.62	34.50
1	Andhra Pradesh	10.96	52	141.53	39.20
2	Assam	33.89	54	135.65	16.90
3	Bihar	34.06	48	125.98	38.20
4	Chhattisgarh	44.61	48	83.85	38.00
5	Gujarat	21.54	29	112.84	32.50
6	Haryana	11.64	46	196.89	25.70
7	Jharkhand	40.84	33	132.04	30.30
8	Karnataka	24.53	34	142.40	35.80
9	Kerala	9.14	169	314.88	37.30
10	M.P.	37.74	33	105.22	33.50
11	Maharashtra	24.22	42	117.36	34.50
12	Orissa	35.69	87	117.43	31.30
13	Punjab	7.66	52	198.64	32.00
14	Rajasthan	16.05	35	159.45	25.40
15	Tamil Nadu	15.83	111	169.93	50.00
16	UttarPradesh	30.4	51	133.06	29.60
17	West Bengal	22.52	83	120.92	46.90

***Source: Col.-1,** Planning Commission 2011-12, Based on Uniformed Recall Period. **Col.-2 to 4,** -68th Round, NSS Report No.554 Employment &Unemployment Situation in India 2011-*

योजना आयोग के ग्रामीण भारत में 2011–12 के गरीबी के आकड़ों से स्पष्ट हैं कि ग्रामीण भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण गरीबी 25.7 प्रतिशत हैं जबकि राज्यों में सबसे अधिक गरीबी छत्तीसगढ़ राज्य में 44.61 प्रतिशत हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बाद सबसे अधिक गरीबी क्रमशः झारखण्ड (40.84 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (37.34 प्रतिशत), उड़ीसा (35.69 प्रतिशत), बिहार (34.06 प्रतिशत), असम (33.89 प्रतिशत) तथा उत्तर प्रदेश राज्य में 30.4 प्रतिशत गरीबी हैं। इसके विपरीत सबसे कम गरीबी पंजाब, केरल, आन्ध्र प्रदेश तथा हरियाणा राज्य में क्रमशः 7.66, 10.96 तथा 11.64 प्रतिशत गरीबी हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में गरीबी 15 से 25 प्रतिशत गरीबी हैं **(Table-5.7, Map No.- 5.1)**।

xkeh.k jkstxkj vkj Je ij fuHkj tul[;k **(Rural Employment and Population Dependent on Labour)**

खाद्य पहुँच आय तथा नियमित रोजगार के पहुँच पर निर्भर करता है। कुछ दशक से श्रम का नियमित या स्थायी रोजगार से अस्थायी या अनियमित रोजगार की ओर प्रवृति बढ़ी है अर्थात श्रम का अनियतिकरण (Casualisation) हुआ है और श्रमिकों को अब दैनिक आधार पर रोजगार और बेरोजगारी के बीच गतिशीलन हुआ है। इसलिए खाद्य पहुँच की निर्भरता के अध्ययन के लिए दैनिक बेरोजगारी दर (Daily Unemployment Rate) सबसे अच्छा माप होता हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण के भारत में रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति सम्बन्धी रिर्पोट 2011–12 के अनुसार राज्यों में दैनिक बेरोजगारी दर केरल में अधिकतम 16.9 प्रतिशत, तमिलनाडु में 11.1 प्रतिशत तथा गुजरात में न्यूनतम 2. 9 प्रतिशत के मध्य परिवर्तित होती है। दैनिक बेरोजगारी की दर का स्तर गरीबी के हेड काउंट अनुपात से सम्बंधित नहीं है क्योंकि इसके अनेक कारण है जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) दैनिक बेरोजगारी स्तर में सम्मिलित नहीं होती। गरीब जो कुछ भी कार्य पाते है वे करते है और वे बेरोजगार रहने में सामर्थ नहीं होते क्योंकि उनको अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त भोजन को खरीदने के लिए उन्हे मुद्रा की आवश्यकता होती है। प्रायःअशिक्षित ग्रामीण गरीबों की अपेक्षा शिक्षित लोगों के मध्य बेरोजगारी की दर वास्तव में उच्च होती है। कभी–कभी जब श्रमिक का शोषण (जब कम मजदूरी पर श्रमिक अधिक कार्य करता है) होता है तब बेरोजगारी बहुत कम तथा गरीबी अधिक विस्तृत होगी। दूसरा कारण जब श्रमिक संघो के रुप में संगठित होते है जैसा कि केरल राज्य में तो, वे मजदूरी की दर को बढ़ाते है और इसके कारण रोजगार देने वाला अधिक श्रमिकों को रोजगार पर नही लगाता है जबकि गरीबी अच्छी मजदूरी तथा सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम (Sefty Net) से कम होती है। केरल में अन्य राज्यों की अपेक्षा बेरोजगारी अधिक है क्योंकि वहाँ पर मजदूरी दर अधिक होने के कारण पर्याप्त कार्य उपलब्ध नहीं होता है। इसके साथ ही बेरोजगारी जनसंख्या के घनत्व तथा कृषि और गैर–कृषि कार्यो की उपलब्धता पर भी निर्भर करती हैं।

जब परम्परागत कृषि सभी श्रमिको को रोजगार देने में सक्षम न हो तो गरीबी उन्मूलन के लिए विशेष रूप से गैर–कृषिगत ग्रामीण रोजगार महत्वपूर्ण होता। सामान्यतः गैर–कृषि रोजगार में कृषि रोजगार की अपेक्षा अधिक मजदूरी प्राप्त होती है। यही एक कारण है कि ग्रामीण पुरुष गांवो में कृषि कार्यो को औरतों के लिए छोड़कर गैर–कृषि कार्य को प्राप्त करने के लिए अधिक दूर चले जाते है। इस प्रकार गरीबी उन्मूलन के लिए न केवल रोजगार की मात्रा बल्कि रोजगार का स्वरुप (Quality) और मजदूरी दर भी महत्वपूर्ण है। अनियमित रोजगार चाहे वह कृषि मे हो या गैर–कृषि में अनिश्चित जीविका (Uncertain Livelihood)में सहायक होता है। अनियत या अस्थायी रोजगार के उच्च स्तर से रोजगार से बाहर होने का जोखिम भी अधिक तथा अल्पकालिक खाद्य के पहुँच और खाद्य असुरक्षा का जोखिम भी अधिक होता है।

NSSO के 68 वें चक्र के भारत में रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति सम्बंधी रिर्पोट 2011–12 के आकड़ों के विश्लेषण के अनुसार तमिलनाडु में श्रम पर निर्भर जनसंख्या या परिवार का प्रतिशत अधिकतम 50 प्रतिशत है। इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल (46.9 प्रतिशत), आन्ध्र प्रदेश (39.2

प्रतिशत) तथा बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में 38 से 33 प्रतिशत ग्रामीण परिवार श्रम आय पर निर्भर है और इसके विपरीत श्रम आय पर निर्भर परिवारों का सबसे कम प्रतिशत असम राज्य में 16.9 प्रतिशत है जबकि इसके बाद राजस्थान (25.4), हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश का है। यद्यपि जिन राज्यों में श्रम आय पर निर्भर परिवारों का प्रतिशत अधिक है उन राज्यों मे ग्रामीण गरीब (श्रम परिवारों की अधिक संख्या के कारण) अधिक नहीं है, परन्तु जिन राज्यों में श्रम परिवारों का प्रतिशत अधिक है वहां पर 1890 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन से कम उपभोग करने वाले परिवारों के प्रतिशत में कुछ समानता दिखती है अतः कैलोरी अन्तर्ग्रहण, मजदूरी, रोजगार तथा खाद्यान्नों की सापेक्षिक कीमतों पर निर्भर करता**(Table-5.7)** है।

vkl r dykjh vUrxg.k (Average Calorie Intake) :-

NSSO के भारत में पौष्टिक अन्तर्ग्रहण के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण भारत में औसत प्रति व्यक्ति कैलोरी अन्तर्ग्रहण 1972–73 से 1983 में 45 Kcal की गिरावट हुई जबकि 1983 से 1993–94 के बीच 68Kcal तथा 1993–94 से 2004–05 के बीच 106 Kcal की गिरावट आयी है और 2004–05 से 2009–10 के बीच 27 Kcal की कमी हुई है जबकि 2009–10 से 2011–12 के बीच 79 Kcal की वृद्धि हुई है। कैलोरी अन्तर्ग्रहण में यह गिरावट न्यून व्यय वर्गों में भी देखी गयी है। इस कैलोरी अन्तर्ग्रहण में गिरावट की अनेक व्याख्या की गयी है और यह गिरावट प्रत्यक्ष रुप से आनाजों के उपयोग में गिरावट से सम्बंधित (Table- 5.3)

ग्रामीण भारत में NSSOकेपौष्टिक अन्तर्ग्रहण के आकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट हैं कि पंजाब राज्य में अधिकतम 3066 Kcal प्रति उपभोक्ता इकाई प्रतिदिन कैलोरी अन्तर्ग्रहण है। इसके बाद हरियाणा में 2992 Kcal तथा राजस्थान में 2959 Kcal प्रति उपभोक्ता इकाई प्रतिदिन है। सबसे कम प्रति उपभोक्ता इकाई प्रतिदिन कैलोरी अन्तर्ग्रहण गुजरात में 2497Kcalहैं। अनाजों का योगदान कैलोरी अन्तर्ग्रहण में अन्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक है अधिकांश राज्यों में कैलोरी अन्तर्ग्रहण का उच्च स्तर अनाजों के उपभोग के उच्च स्तर से सम्बंधित है। औसत रुप से राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में प्रति उपभोक्ता इकाई प्रतिदिन कैलोरी अन्तर्ग्रहण 2752 Kcal है यद्यपि अनाजोंका उपभोग अधिक जबकि अन्य खाद्य पदार्थो का उपभोग कम होने के कारण अधिकांश राज्यों का औसत कैलोरी अन्तर्ग्रहण राष्ट्रीय स्तर के कैलोरी अन्तर्ग्रहण से कम है। असम, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में कैलोरी अन्तर्ग्रहण राष्ट्रीय स्तर के कैलोरी अन्तर्ग्रहण से कम है।

Table 5.3: Calorie Intake among States in Rural India
Deficient Calorie Intake (Per Cu/Day)

		1	2	3	4	5
S.N.	State/India	Average Per Capita Intake Per Day (Kcal)	Average Intake Per Consumer Unit Per Day (Kcal)	Calorie Intake of the Lowest (5 to 10% Population) Per cu/day (Kcal)	Average Intake of Lower Expenditure Group <Rs.521(< 5% population) Per cu/per day	Percentage of Households Consuming less than1890

	Schedule type -2 (Modified Mixed Recall Period-2011-12)				
	India	2233	2752	2265	2033	5.60
1	Andhra Pradesh	2365	2926	2386	2290	2.20
2	Assam	2170	2617	2132	2029	7.20
3	Bihar	2242	2731	2101	2019	4.10
4	Chhattisgarh	2162	2661	2215	1906	4.20
5	Gujarat	2024	2497	2020	1726	8.80
6	Haryana	2441	2992	2266	2106	2.90
7	Jharkhand	2138	2645	2000	1929	7.30
8	Karnataka	2164	2675	2143	2052	3.80
9	Kerala	2162	2749	1941	1817	9.90
10	M.P.	2234	2711	2053	1970	8.70
11	Maharashtra	2260	2802	2142	1977	4.80
12	Orissa	2215	2750	2319	2127	4.20
13	Punjab	2483	3066	2480	2207	2.40
14	Rajasthan	2408	2959	2416	2073	3.40
15	Tamil Nadu	2052	2560	1924	1665	12.10
16	Uttar pradesh	2200	2717	2263	1997	5.90
17	West Bengal	2199	2710	2251	2054	5.30

Source: Col.-1 -5, 68th Round, NSSO Report No.560: Nutritional Intake of India, 2011-12

यद्यपि कैलोरी अन्तर्ग्रहण का औसत स्तर पर्याप्त है परन्तु निम्न व्यय वर्ग में कैलोरी अन्तर्ग्रहण पर्याप्त नहीं है और यही चिंता का मुख्य विषय है। राज्यों के औसत कैलोरी अन्तर्ग्रहण के उच्च स्तर की तुलना में निम्न व्यय वर्ग (521 रु प्रति व्यक्ति प्रतिमाह से कम– Bottom 5 Percent Population) का कैलोरी अन्तर्ग्रहण आवश्यक मात्रा से कम है। निम्न व्यय वर्ग में सबसे कम प्रति उपभोक्ता इकाई प्रतिदिन कैलोरी अन्तर्ग्रहण तमिलनाडु में 1665 Kcal है, इसके बाद सबसे कम कैलोरी अन्तर्ग्रहण गुजरात में 1726 Kcal, केरला में 1817 Kcal, छत्तीसगढ़ में 1906 कैलोरी, झारखण्ड में 1929 कैलोरी तथा मध्य प्रदेश में 1970 कैलोरी दैनिक प्रति उपभोक्ता इकाई है। इसके विपरीत इस न्यून व्यय वर्ग में (521 रु. से कम) सबसे ज्यादा कैलोरी अन्तर्ग्रहण आन्ध्र प्रदेश में 2290 Kcal है, इसके पश्चात पंजाब (2207 Kcal), उड़ीसा (2127 Kcal) तथा हरियाणा का 2106 Kcal **(Table - 5.3)**है।

3. xjhck d e/; dykjh vUrxg.k (Calorie Intake among the Poorest)

न्यूनतम व्यय वर्ग (Lowest Expenditure Group)के कैलोरी उपभोग का स्तर विभिन्न राज्यों में कैलोरी की कमी या भूख की गहराई (Depth of hunger)को व्यक्त करता है। भूख की गहराई को आहार में आवश्यक मानक से कम कैलोरी के उपभोग के रुप में परिभाषित करते है। कैलोरी में आवश्यक मानक से कम अन्तर, कम भूख को तथा अधिक अन्तर ज्यादा भूख को व्यक्त करता है यदि इसमे कोई अन्तर नहीं है तो यहाँ किसी भूख की स्थिति नहीं है। खाद्य और कृषि संगठन(FAO)100 से 400 कैलोरी के बीच अन्तर के रुप में भूख की गहराई को मापता है। 200 कैलोरी से कम, कमी को बहुत अधिक भूख के रुप में विचार नहीं किया जाता है।

न्यून व्यय वर्ग के औसत प्रति उपभोक्ता इकाई प्रतिदिन कैलोरी अन्तर्ग्रहण के आकड़ों को NSSOके भारत में पौष्टिक अन्तर्ग्रहण रिर्पोट 2011–12 के आकड़ों से लिया गया है। ग्रामीण भारत में न्यूनतम 5 प्रतिशत जनसंख्या का कैलोरी अन्तर्ग्रहण दिखाता है कि 2000Kcal से अधिक प्रति उपभोक्ता इकाई प्रतिदिन कैलोरी अन्तर्ग्रहण केवल आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब,

राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल राज्य में है। ग्रामीण भारत में न्यूनतम 5 प्रतिशत जनसंख्या का उपभोग तमिलनाडु में केवल 1665 Kcal, गुजरात में 1726 Kcal तथा केरल में 1817 Kcal अन्तर्ग्रहण है जो सभी राज्यों में न्यूनतम है। जबकि छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 5 प्रतिशत जनसंख्या का कैलोरी अन्तर्ग्रहण 1900 से 2000 Kcalके बीच है (Table - 5.3, Map No. 5.3)।गुजरात, तमिलनाडु तथा केरल में 2011–12 में न्यून व्यय वर्ग में कम कैलोरी अन्तर्ग्रहण के जो कुछ भी कारण हो लेकिन हम इस तथ्य से सहमत है कि जिन राज्यों में प्रतिव्यक्ति अनाजों की उत्पादन अधिक है वहाँ न्यूनतम 5 प्रतिशत जनसंख्या में कैलोरी अन्तर्ग्रहण भी अधिक है।

4. 1890 dSyksjh ls de miHkksx djus okyh tula[;k dk izfr'kr (Percentage of population consuming less than 1890 Kcal)

भूख (Hunger) को सामान्यतः अपर्याप्त खाद्य ऊर्जा उपभोग के कारण कष्टपूर्ण या असुखद (Painful or Uncomfortable) अनुभूति या संवेदना के रूप में समझा जाता है तथा इसे वैज्ञानिक रूप से खाद्य के अभाव (Food Deprivation) के रूप में व्यक्त किया जाता है।

1890 कैलोरी प्रति उपभोक्ता इकाई प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाले व्यक्तियों को उतना ही अधिक भूखा (Hungry) विचार किया जाता है, जितना ही अधिक उसका उपभोग ICMR द्वारा निर्धारित खाद्य पर्याप्तता के मानक की अपेक्षा कम होता है। 1890 कैलोरी प्रति उपभोक्ता इकाई प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत भूख के विस्तार (Spread of hunger) को व्यक्त करता है । लगभग 29.2 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या 2430 कैलोरी प्रति उपभोक्ता इकाई प्रतिदिन से कम उपभोग करती है। ग्रामीण भारत का औसत कैलोरी उपभोग 2752 कैलोरी प्रति उपभोक्ता इकाई प्रतिदिन है। इसलिए इसका विश्लेषण और मैपिंग के लिए न्यून पर्याप्तता (Lower Adequecy) मानक का प्रयोग करते है और यह 1890 Kcal मानक स्तर 2700 Kcalके अन्तर्राष्ट्रीय औसत कैलोरी उपभोग स्तर का लगभग दो प्रमाप विचलन (Two Standard Deviation)कम है। एक व्यक्ति या मनुष्य द्वारा इस न्यूनतम उपभोग स्तर से कुछ भी कम मात्रा उपभोग का सम्भवतः कुपोषण के दीर्घकालीन बुरे प्रभाव का कारण होता है।

NSSO के 2011–12 में 68 वें चक्र के आकड़ें दिखाते है कि ग्रामीण भारत में लगभग 5.6 प्रतिशत जनसंख्या 1890 कैलोरी प्रति उपभोक्ता इकाई प्रतिदिन से कम उपभोग करती है। जबकि तमिलनाडु राज्य में भूख का विस्तार (1890 Kcal से कम उपभोग) सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या का 12.1 प्रतिशत है इसके बाद केरल राज्य में (9.9 प्रतिशत), गुजरात (8.8प्रतिशत),मध्य प्रदेश (8.7 प्रतिशत) तथा झारखण्ड राज्य में (7.3 प्रतिशत) है। इन चार राज्यों में भूख की गहनता (Depth of hunger)जिसे न्यूनतम 5 प्रतिशत जनसंख्या के औसत कैलोरी उपभोग के रुप में मापा जाता है, भी अधिकतम है। अतः इन अनाजों के कम उत्पादन वाले राज्यों में भूख के विस्तार के साथ भूख की गहनता भी अधिक पायी जाती है। इन राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में आय के मुख्य स्रोत के रुप में श्रम आय पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत भी 30 प्रतिशत से अधिक है जैसे तमिलनाडु में श्रम आय पर निर्भर जनसंख्या 50 प्रतिशत है।

जबकि जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन निर्धारित दैनिक आवश्यकता से अधिक है वहाँ पर भूख का विस्तार भी कम है जैसे पंजाब, हरियाणा, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन आधिक्य है और इनमें भूख का विस्तार भी अपेक्षाकृत कम है।

dSyksjh vUrxzg.k vkSj xjhch **(Calorie Intake and Poverty)**

हेंड काउंट अनुपात द्वारा निर्धारित गरीबी के स्तर और न्यूनतम कैलोरी मानक **(1890 Kcal)** से कम कैलोरी उपभोग करने वाली जनसंख्या के बीच एक धनात्मक और महत्वपूर्ण सम्बंध की प्रत्याशा तर्कसंगत है। जिस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत अधिक होगा वहां पर 1890 से कम कैलोरी उपभोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी अधिक होगी। इसी प्रकार यह आशा करना भी तर्कसंगत है कि गरीबी का हेडकाउंट अनुपात और विभिन्न राज्यों में न्यूनतम पाँच प्रतिशत

जनसंख्या **(Lowest 5**प्रतिशत) के मध्य कैलोरी अन्तर्ग्रहण में ऋणात्मक सम्बंध होगा अर्थात जिस राज्य में गरीबी कम होगी उस राज्य में न्यूनतम व्यय वर्ग की जनसंख्या का कैलोरी उपभोग अधिक होगा। यद्यपि आकड़े इस प्रकार के सम्बंध को नहीं दिखाते है कि सबसे गरीब राज्य में 1890 कैलोरी से कम उपभोग करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत उच्च होगा।

जैसा कि छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रशित 44.61 प्रतिशत है जबकि 1890 कैलोरी प्रति उपभोक्ता इकाई प्रतिदिन से कम उपभोग करने वालो का प्रतिशत 4.2 प्रतिशत है, उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 35.69 है जबकि 1890 कैलोरी प्रति उपभोक्ता इकाई से कम उपभोग करने वाले का प्रतिशत केवल 4.2 है इसी प्रकार मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत क्रमशः 37.74 प्रतिशत, 34.6 प्रतिशत तथा 30.4 प्रतिशत है जबकि 1890 कैलोरी प्रति उपभोक्ता इकाई प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 8.7 प्रतिशत, 4.1 प्रतिशत तथा 5.9 प्रतिशत है। इसके विपरीत तमिलनाडु, गुजरात तथा केरल राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालो का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है, में 1890 कैलोरी प्रति उपभोक्ता इकाई प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत (क्रमशः 12.1, 8.8 और 9.9 प्रतिशत) अपेक्षाकृत अधिक है। ये वे राज्य है जहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी अधिक कुशल है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का भी एक बड़ा नेटवर्क है इसके बावजूद इन राज्यों में न्यूनतम पाँच प्रतिशत की जनसंख्या के कैलोरी उपभोग पर अधिक प्रभाव दिखाई नहीं देता।

गरीबी का हेड काउंट अनुपात आपदा तथा खाद्य असुरक्षा का सामना करने के लिए व्यक्ति की क्षमता का एक महत्वपूर्ण माप है। सूखे या आकाल के दौरान खाद्यान्न की कमी के समय संतुलित आहार लेने की क्षमता, स्वास्थ्य सहायता प्राप्त करना और अपने को स्वस्थ रखना जैसे अनेक कार्य गरीबी के साथ किये जाते है। राज्यों द्वारा सब्सिडी (सहायकी) प्राप्त खाद्यान्नों, स्वच्छ पीने का पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, और फ्री शिक्षा के द्वारा आय हस्तान्तरण से वास्तविक आय में सुधार होता है और इस प्रकार गरीबी आय से महत्वपूर्ण रुप से सम्बंधित होती है। वास्तव में NSSOके आकड़े इस पर बल देते है कि निम्न व्यय वर्ग का कैलोरी अन्तर्ग्रहण उच्च व्यय वर्ग के कैलोरी अन्तर्ग्रहण से काफी कम है तथा यह स्पष्ट है कि न्यूनतम उपभोग व्यय वर्ग का कैलोरी अन्तर्ग्रहण अन्य की अपेक्षा ज्यादा कम है।
विभिन्न राज्यों में गरीबी के स्तर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जिन राज्यों में कृषि में विविधता है उन राज्यों में गरीबी भी सापेक्षिक रूप में कम है क्योंकि कृषि में विविधिकरण से कृषि श्रमिकों को अधिक रोजगार प्राप्त होता है। जिन राज्यों में गरीबी 22 प्रतिशत से कम अर्थात राष्ट्रीय औसत ग्रामीण गरीबी से कम है उन राज्यों में गैर–आनाज फसल तथा पशु उत्पादन अधिक है जैसे पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान तथा गुजरात राज्यों में अनाजों के अलावा दूध, दालें, फल, सब्जियां तथा मत्स्य उत्पादन की ओर अन्य राज्यों के अपेक्षा ज्यादा विविधिकरण है।

fu'd"k ,o l>ko (Conclusion and Suggestion):-

इस प्रकार यह विश्वास योग्य है जिन राज्यों में खाद्यान्नों का उत्पादन कम होता है वहाँ पर निम्न आय वर्ग कम कैलोरी अन्तर्ग्रहण की समस्या से प्रभावित होता है यद्यपि उस राज्य का औसत उपयोग पर्याप्त होता है। न्यूनतम 5 प्रतिशत जनसंख्या के कैलोरी अन्तर्ग्रहण के साथ–साथ औसत रुप से राज्य में कैलारी अन्तर्ग्रहण प्रति व्यक्ति अनाजों के ष्ुद्ध उत्पादन से महत्वपूर्ण रुप में सम्बंधित है। इसका दो मुख्य कारण है– जो पर्याप्त कैलोरी अन्तर्ग्रहण में सक्षम बनती है, पहला, उत्पादन के क्षेत्रों में कीमते सम्भवतः कम होती है जो गरीबो को पर्याप्त अन्तर्ग्रहण में सक्षम बनती है, दूसरा पर्याप्त जीविका अवसर वाले क्षेत्रों में न्यूनतम व्यय वर्ग की पर्याप्त या अधिक कैलोरी अन्तर्ग्रहण की सम्भावना भी अधिक होती है।

नीति के स्तर पर यह निश्चित है कि उच्च गरीबी स्तर वाले क्षेत्र दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन भूख

(Chronic and Transitory Hunger) की समस्या से भी प्रभावित है। न्यूनतम व्यय वर्ग की आवश्यकता का स्वरुप भी प्रायः अल्पकालिक हो सकता है। निष्कर्षो के दिये होने पर कि कम कैलोरी उपभोग करने वाली जनसंख्या (Calorie Deficient Population) उन क्षेत्रों में निवास करे जहाँ गरीबी का हेड काउंट अनुपात उच्च हो, आवश्यक नहीं है, तो यह अच्छा होगा कि दीर्घकालीन या अल्पकालीन खाद्य असुरक्षा के लिए वैकल्पिक माप का विकास किया जाए, जो अन्य जोखिम चरो (Vulnerability Factors) जैसे कि दिहाड़ी या दैनिक मजदूर (Casual Labour), जनजातीय जनसंख्या, पोषणीय दिशा निर्देश (Nutritional Guideline) जैसे कैलोरी, प्रोटीन कुपोषण आदि पर आधारित होने के साथ ही केवल गैर–कृषि विविधिकरण तथा कृषि में विविधिकरण की आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से गरीबी को समाप्त किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त अधोसंरचना, साक्षरता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मजदूरी और रोजगार ये सभी चर गरीबी को समाप्त करने में केवल सहायता करते है।

Reference:-

1. Himanshu (2007): "Recent Trends in Poverty and Inequality: Some Preliminary Results' Economic and Political Weekly, February. 10,
2. M. S. Swaminathan Research Foundation & World Food Programme (2002): "Food Insecurity Atlas of Urban India' Printed byTTK Healthcare Limited – Printing Division 328 GST Road, Chormepet Chennai – 600044
3. NSSO 68th Round Report NO.555: "Level and Pattern of Consumer Expenditure2011-12श, National Statistical Organization, Ministry of Statistics and Programme Implementation Government of India.
4. NSSO 68th Round, Report No.554: "Employment & Unemployment Situation in India 2011-12', National Statistical Organization, Ministry of Statistics and Programme Implementation Government of India.
5. NSSO 68th Round, Report No.560: "Nutritional Intake of India- 2011-12', National Statistical Organization, Ministry of Statistics and Programme Implementation Government of India.
6. Rajuladevi. A. (2001): "Food Poverty and Consumption among Landless Labour Households', Economic and Political Weekly, 35(28), 1659-1667.